डेरा बाबा राम गिर बनाम हरियाणा राज्य, आदि(तुली, नयायाधिपती)

के.एस.के.

नागरिक विविध

बल राज तुली, नयायाधिपती के सामने।

डेरा बाबा राम गिर,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि,-प्रतिवादी।

1971 की सिविल रिट संख्या 404।

13 दिसंबर 1971.

पंजाब भूमि राजस्व (अधिभार) अधिनियम (1954 का XXXVI) - धारा 2 - पंजाब भूमि राजस्व (विशेष शुल्क) अधिनियम (1958 का VI) - धारा 3 - मुआफिदार के तहत अधिभार और विशेष शुल्क का भुगतान - क्या ऐसा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

निर्धारित किया गया कि पंजाब भूमि राजस्व (अधिभार) अधिनियम, 1954 की धारा 2 और पंजाब भूमि राजस्व (विशेष शुल्क) अधिनियम, 1958 की धारा 3 की भाषा स्पष्ट है, जिसके अनुसार केवल एक जमींदार जो भूमि राजस्व का भुगतान करता है, न कि एक भूस्वामी, जिसके भू-राजस्व का मूल्यांकन किया गया है, अधिभार और विशेष शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। जिस व्यक्ति को मुआफ़ी प्रदान की जाती है, वह उस भूमि का मालिक होता है जिसके पक्ष में भू-राजस्व जारी किया जाता है, अर्थात, वह सरकार को किसी भी भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि भू-राजस्व की राशि का मूल्यांकन किया जा सकता है। . एक मुआफ़िदर भू-राजस्व का समनुदेशिती भी नहीं है। इसलिए एक मुफ़िदार एक ज़मींदार है जो भू-राजस्व का भुगतान नहीं करता है, उपरोक्त अधिनियमों के तहत किसी भी अधिभार या विशेष शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, प्रार्थना करते हुए कि वह प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा याचिकाकर्ता डेरा की भूमि पर सरचार्ज और विशेष अधिभार के लेवी को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी, मैंडामस या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करे।

याचिकाकर्ता के वकील ए.एन.मित्तल।

प्रतिवादियों की ओर से हरि मित्तल, उप महाधिवक्ता, (हरियाणा)।

निर्णय.

तुली, नयायाधिपती। -याचिकाकर्ता-डेरा को भू-राजस्व की मुआफ़ी "पटियाला के तत्कालीन राज्य द्वारा पोह 19, संबत 1960 बीके, 2 जनवरी 1904 ई. के बराबर एक सनद द्वारा प्रदान की गई थी। यह सहायक निपटान अधिकारी, पटियाला सर्कल द्वारा पारित आदेश और निपटान आयुक्त, पटियाला के आदेश पर आधारित था। अनुदान की शर्तों को बताने वाले सहायक निपटान अधिकारी, पटियाला सर्कल के आदेश की एक प्रति उत्तरदाताओं द्वारा अनुलग्नक आर 2/III के रूप में उनके रिटर्न के साथ दायर की गई है।कार्यालय द्वारा इसका अंग्रेजी में किया गया अनुवाद बिल्कुल सही नहीं है। सही अनुवाद इस प्रकार है:-

“(1) पहले कुल जमाई रु. 1,106 जिसमें 1,006 रुपये की भू-राजस्व और 100 रुपये की विविध माँगों सहित स्वाई (उपकर) शामिल थे। पूरे गाँव की मुआफ़ी के कारण, बिस्वेदार केवल सवाई और अन्य विविध माँगों का भुगतान करता है।

(2) संशोधित कुल मांग रु. 1,750 रुपये मिलाकर। भू-राजस्व के कारण 1,523 रु. स्वाई के खाते में 227 रु. स्वाई राशि में से रुपये काटने के बाद जो राशि बचेगी, उसका भुगतान बिस्वेदार करेगा। लम्बरदारी के नाम पर 70 रु. मुआफी की श्रेणी में 95 (जो भू-राजस्व का 6-4-0 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया है) खरीफ 1960 से प्रभावी तथा बिस्वेदार की इच्छानुसार अतिरिक्त सरसरी भाग की दर से खेती की जमीन पर प्रति एकड़ 2 पाई तय की जा सकती है। मालिक जैसा कोई किरायेदार नहीं होता। पूरे गाँव का क्षेत्रफल 19,098 बीघे खाम है जिसमें से 12,915 बीघे खाम की खेती होती है और 6,183 बीघे खाम बंजर भूमि पर है। पूरे क्षेत्र में से 12,915 बीघे खाम को बच्छ में शामिल किया गया है जबकि 6,183 बीघे खाम क्षेत्र को बच्छ से बाहर रखा गया है।

(3) पूरा गांव सरकार की ओर से बिस्वेदार को मुआफ है, जिसकी मंजूरी एक अलग फाइल पर दी गई है। जमींदारी के संबंध में कोई मुआफ़ी नहीं है।

(4) कोई गैर-अधिभोगी किरायेदार नहीं है।

(5) ननकार नहीं है।

(6) पहले कोई मालबा (ग्राम व्यय) निर्धारित नहीं था। भविष्य में भी ग्राम व्यय मद में किसी धनराशि का निर्धारण न किया जाय।

(7) पिछली किस्तें खरीफ में 3/5वीं और रबी फसल में 2/5वीं तय की गई थीं और उन्हें भविष्य में भी जारी रखा जाना चाहिए।

(8) चूँकि पूरे गाँव का स्वामित्व एक ही मालिक के पास है, इसलिए गाँव को खालिस जमींदारी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।“

सेटलमेंट कमिश्नर, पटियाला, दिनांक 2 जनवरी, 1904 के आदेश की एक प्रति, (अनुलग्नक आर. 2/II) इस प्रकार है: -

“इस गांव का राजस्व कुछ समय के लिए मान्यता प्राप्त संरक्षक के नाम पर वहां स्थित डेरा रामगीर को जारी किया जाता है। एएसओ द्वारा प्रस्तावित अनुसार उपकर एकत्र किया जाएगा। मुआफ़ी एक धर्मार्थ और धार्मिक संस्था के रूप में डेरा के उचित रखरखाव के लिए सशर्त है।“

हरजस गिर के प्रबंधन के तहत डेरा रामगीर को पटियाला सरकार द्वारा जारी की गई सनद मुआफ़ी का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है: -

“कानून के अनुसार पहली बार किए गए वर्तमान समझौते में मुआफियों की पूछताछ और समीक्षा के परिणामस्वरूप, जमीन के संबंध में नकद के लिए भू-राजस्व की मुआफी (सभी 19 वर्गों में) आपको नीचे दिए गए बयान में दिए गए विवरण के अनुसार प्रदान की जाती है: —

इसलिए, यह सनद दी जाती है और आपको मुआफ़ी के नियमों और शर्तों का पालन करते हुए इस पूर्ण मुआफ़ी का आनंद लेने का आदेश दिया जाता है।“

सनद में उल्लिखित कथन में मुआफ़ी के आनंद की शर्त इस प्रकार दर्ज की गई है: -

“इस गांव के जमाई को डेरा राम गिर के वर्तमान प्रबंधक के पक्ष में रिहा किया गया है। मुआफ़ी की शर्त ये है कि डेरा धार्मिक और धर्मार्थ संस्था के रूप में कायम रहे। ”

इन दस्तावेजों के आधार पर, पटियाला राज्य और पेप्सू राज्य के अस्तित्व की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता-डेरा से कभी भी कोई भू-राजस्व नहीं लिया गया। पंजाब विधानमंडल ने पंजाब भूमि राजस्व (अधिभार) अधिनियम, 1954 (इसके बाद इसे 1954 अधिनियम कहा जाएगा) पारित किया। , धारा 2 में भू-राजस्व पर अधिभार लगाने का प्रावधान है, जो इस प्रकार है: -

“ वर्ष 1953-54 की रबी फसल से प्रभावी, या, जहां यह अधिनियम धारा 1 की उप-धारा (3) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र में लागू होता है, ऐसी फसल से प्रभावी होता है राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम,

1887 (1887 का अधिनियम XVII) में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, प्रत्येक भू-स्वामी जो दस रुपये से अधिक भू-राजस्व का भुगतान करता है, वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि भू-राजस्व के रूप में उसके द्वारा देय राशि तीस रुपये से अधिक नहीं है, तो भू-राजस्व के एक-चौथाई की सीमा तक अधिभार, और जहां उसके द्वारा देय राशि तीस रुपये से अधिक है, तो भू-राजस्व का दो-पांचवां हिस्सा।

बशर्ते कि अधिभार लगाने से किसी जागीर या भू-राजस्व के किसी असाइनमेंट के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी।

(2) अधिभार तब तक वसूला और लगाया जाता रहेगा जब तक इस अधिनियम के प्रारंभ में या उस क्षेत्र के मामले में प्रचलित भू-राजस्व का मूल्यांकन किया जाता है जिसमें यह अधिनियम उप-धारा(3) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा लागू होता है, ऐसी अधिसूचना की तिथि पर प्रचलित धारा 1 लागू रहेगी।

(3) अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी भूमि-स्वामी, जिसकी भूमि एक से अधिक पटवारियों के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, और जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले, किसी भी क्षेत्र में लागू नहीं हुआ है, जैसा भी मामला हो ऐसी जानकारी दिए जाने पर, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से या उक्त तिथि से तीस दिनों के भीतर, प्रत्येक राजस्व संपत्ति के पटवारी को उसके द्वारा देय कुल भू-राजस्व के विवरण की लिखित जानकारी देनी होगी जिसमें कोई ऐसी होल्डिंग का हिस्सा स्थित है, और उसकी एक प्रति क्षेत्राधिकार वाले तहसीलदार को भी प्रस्तुत करेगा।

(3ए) यदि कोई भू-स्वामी पूर्वगामी उप-धारा में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करता है जो भौतिक विवरणों में गलत है, तो उससे इस अधिनियम के तहत वसूली योग्य अधिभार की राशि का बारह गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है:

बशर्ते कि एक भूमि मालिक को आवश्यक जानकारी प्रदान की गई मानी जाएगी यदि वह इसे पंजाब भूमि राजस्व (अधिभार) (संशोधन) अधिनियम, 1957 के प्रारंभ होने के एक महीने के भीतर प्रस्तुत करता है।

(4) अधिभार और जुर्माना, यदि कोई हो, वह इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से वसूली योग्य होगा।“

1958 में, पंजाब भूमि राजस्व (विशेष शुल्क) अधिनियम, 1958 (इसके बाद 1958 अधिनियम कहा जाएगा) अधिनियमित किया गया था, जिसकी धारा 3 में विशेष शुल्क लगाने का प्रावधान था और यह धारा इस प्रकार है: -

(5) कृषि वर्ष 1957-58 की रबी फसल के प्रभाव से, या, जहां यह अधिनियम धारा 1 की उपधारा (3) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र में लागू होता है, राज्य में ऐसी फसल के प्रभाव से सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है, और पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का अधिनियम संख्या XVII) में किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, प्रत्येक भूमि मालिक जो पचास रुपये से अधिक भू-राजस्व का भुगतान करता है, वह अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार उस पर विशेष शुल्क भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। “

इन दोनों अधिनियमों के तहत, अधिभार और विशेष शुल्क उस भूस्वामी द्वारा देय होते हैं जो भू-राजस्व का भुगतान करता है। अधिभार की दर भुगतान किए गए भू-राजस्व की राशि पर निर्भर करती है, जबकि विशेष शुल्क की दर एक भू-स्वामी द्वारा भुगतान की गई पचास रुपये से अधिक की भू-राजस्व की राशि पर एक समान होती है, जिसमें 1954 अधिनियम के तहत लगाया गया अधिभार भी शामिल होता है। 1970 की ख़रीफ़ फसल के लिए, याचिकाकर्ता-डेरा को 542.76 रुपये की अधिभार राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। और उपरोक्त अधिनियमों के अनुसार विशेष शुल्क रु. 4,601.43 और इन दो मांगों को वर्तमान रिट याचिका में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि याचिकाकर्ता-डेरा एक भूस्वामी नहीं है जो भू-राजस्व का भुगतान करता है और इसलिए, 1954 अधिनियम की धारा 2 या 1958 अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत नहीं आता है।

(2) उत्तरदाताओं की ओर से लिखित बयान दायर किया गया है, जिस पर एक प्रतिकृति भी दायर की गई है।

(3) मामले में निर्धारण का मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता-डेरा एक भू-स्वामी है जो भू-राजस्व का भुगतान करता है क्योंकि यह केवल ऐसा भूस्वामी है जो ऊपर उल्लिखित दो अधिनियमों के तहत अधिभार और विशेष शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़, यानी सहायक निपटान अधिकारी का आदेश, निपटान आयुक्त का आदेश और डेरा को जारी की गई सनद, यह दर्शाती है कि संपूर्ण भू-राजस्व डेरा के पक्ष में जारी किया गया था और डेरा गाँव का

एकमात्र ज़मींदार था, इसलिए उसके पक्ष में भू-राजस्व जारी करने का प्रभाव यह था कि डेरा राज्य को किसी भी भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। रिटर्न में कहा गया है कि वर्ष 1967-68 ई. के दौरान डेरा ने रुपये का भुगतान किया. भू-राजस्व के कारण 158.00 रुपये का भुगतान किया और रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उस मांग का भी भुगतान किया जिसे इस याचिका में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान मांग का भुगतान राज्य द्वारा जबरदस्ती तरीकों से इसकी वसूली से बचने के लिए किया गया था क्योंकि इस न्यायालय ने उस मांग की वसूली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 1967-68 में भूलवश भू-राजस्व का भुगतान कर दिया गया। रुपये का भुगतान. वर्ष 1967-68 के लिए भू-राजस्व के कारण 158.00, याचिकाकर्ता-डेरा को इस आधार पर अधिभार या विशेष शुल्क का भुगतान करने के अपने दायित्व पर विवाद करने से नहीं रोकता या रोकता नहीं है कि यह उससे वसूली योग्य नहीं है।

(4) अधिभार और विशेष शुल्क के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता-डेरा की देनदारी निर्धारित करने के लिए, 'मुआफ़ी अनुदान की प्रकृति और विशेषताओं को समझना आवश्यक है। विल्सन द्वारा लिखित न्यायिक और राजस्व शर्तों की शब्दावली, 1940 संस्करण में, मुआफ़ी का अर्थ इस प्रकार बताया गया है-

"क्षमा किया गया, क्षमा किया गया: उपसर्ग, क्षमा करना, राज्य की मांगों से छूट या छूट: मूल्यांकन से मुक्त भूमि का अनुदान: यह शब्द आम तौर पर भूमि, माल के रूप में शुल्क या कर से छूट या मुक्त का संकेत देने के लिए उपयोग में है। आदि: इसमें पूर्व में जमींदारों और सरकार के राजस्व अधिकारियों द्वारा दिए गए एक विशेष अनुदान को भी निर्दिष्ट किया गया था, जो वंशानुगत और हस्तांतरणीय हो गया था, और उन भूमियों पर भी लागू किया गया था जो सेवा की शर्त पर राजस्व से मुक्त रखी गई थीं।“

(5) ***शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाम करम सिंह***[1] में, एक डिवीजन बेंच ने कहा-

“मुआफी और जागीर के बीच अंतर यह है कि मुआफी और जागीर में मालिक को भू-राजस्व की छूट दी जाती है, जबकि बाद में भू-राजस्व का एक असाइनमेंट होता है, जिसे एकत्र किया जाता है और जागीरदार को भुगतान किया जाता है। जागीरदार बाद में संपत्ति का अधिग्रहण

[1] A.I.R. 1930 Lab. 46.

कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो अनुदान तकनीकी रूप से 'मुआफी' बन जाता है, हालांकि इसे हमेशा जागीर के रूप में दिखाया जाता है।“

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस भूस्वामी को मुआफ़ी प्रदान की गई है, वह किसी भी राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, उसे भू-राजस्व देने वाला जमींदार नहीं कहा जा सकता। विधायिका को मुआफ़दारों और मुआफ़ी अनुदानों के अस्तित्व के बारे में अच्छी तरह से पता था और यदि इसका इरादा था, जैसा कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि मूल्यांकन किए गए भू-राजस्व के आधार पर अधिभार और विशेष शुल्क लगाया जाए। किसी भूस्वामी ने वास्तव में भू-राजस्व का भुगतान किया है या नहीं, उस इरादे को स्पष्ट करने के लिए एक प्रावधान किया जाना चाहिए था। 1954 अधिनियम की धारा 2 और 1958 अधिनियम की धारा 3 की भाषा इस संदर्भ में स्पष्ट है कि केवल एक भूस्वामी जो भू-राजस्व का भुगतान करता है, न कि वह भूस्वामी जिसके संबंध में भू-राजस्व का मूल्यांकन किया जाता है, अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। और विशेष शुल्क. पुनः, 1954 अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के प्रावधान में, मुआफ़िदरों के संबंध में एक प्रावधान किया जा सकता है, जैसा कि जागीरों और भू-राजस्व के असाइनमेंट के संबंध में किया गया है। एक मुआफ़िदर भू-राजस्व का समनुदेशिती नहीं है। वह मालिक है जिसके पक्ष में भू-राजस्व जारी किया जाता है, अर्थात, वह सरकार को किसी भी भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि भू-राजस्व की राशि का मूल्यांकन किया जा सकता है।

(6) मुआफ़ी अनुदान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मुफ़िदार एक ज़मींदार है जो भूमि राजस्व का भुगतान नहीं करता है और इसलिए, 1954 अधिनियम के तहत किसी भी अधिभार या 1958 अधिनियम के तहत विशेष शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता-डेरा से की गई ऐसी रकम की मांग अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

(7) ऊपर दिए गए कारणों से, मैं इस रिट याचिका को स्वीकार करता हूं और याचिकाकर्ता-डेरा से 1970 की ख़रीफ़ फसल के लिए किए गए अधिभार और विशेष शुल्क के भुगतान की मांग को रद्द करता हूं। चूंकि मुद्दा कठिनाई से मुक्त नहीं था, इसलिए पक्षकार हैं अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा